(c) whether the rise in their emoluments granted in the past years any relationship to the rise in pay, dearness allowances and compensatory allowance granted to the other full-time employees of the Scheme during the period;

(d) if the rise in the emoluments of the former is disproportionately low compared to the other staff of the Scheme, the justifications for this differential treatment except for the fact that they are part-time workers; and

(e) the ratio in the numbers of these two categories of part-time employees and the other full-time employees of class III and upward of the scheme?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shinde): (a) A Depot Manager gets a fixed remuneration of Rs. 50 per mensem and Depot Assistant Rs. 25 per mensem as fixed in 1959.

(b) There has been no increase in these remunerations. However, since 1st November, 1962, they are allowed weekly off or wages in lieu thereof on pro-rata basis, if they are asked to work on the weekly off day.

(c) and (d). Depot Staff is employed on part-time basis, for the morning or evening shift. This remuneration is in no way connected with the rise in the cost of living index or with the pay and allowances of regular Government servants.

(e) Approximately 2 : 1.

12.17 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

REPORTED CONCENTRATION OF PAKISTANI TROOPS ON RAJASTHAN, PUNJAB AND JAMMU AND KASHMIR BORDERS

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : मैं बलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

"राजस्थान, पंजाब तथा जम्मू और काश्मीर की सीमाओं पर पाकिस्तानी सेना के जमाव के समाचार।"

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan): Government are aware of the presence of Pakistani troops on the Pakistan side of the Rajasthan, Punjab and Jammu borders with West Pakistan. A careful watch is kept on the situation across our borders.

श्री यशपाल सिंह : क्या माननीय प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान भुट्टो साहब के उस वक्तव्य की ओर गया है, जो उन्होंने पाकिस्तान के अन्दर दिया और कहा कि हमने ताशकन्द के अन्दर इस तरह का कोई वायदा नहीं किया है कि वे काश्मीर के मामले के हल के बिना कोई हथियार नहीं उठायेंगे ? हमने ताशकन्द में युद्ध न करने का वायदा नहीं किया है। अगर इस वक्तव्य की ओर सरकार का ध्यान गया है तो सरकार इस पर क्या उपाय कर रही है ?

Shri Y. B. Chavan: Certainly we have seen the statements made by some of the Pakistani leaders, including Mr. Bhutto. Possibly they are trying to put a wrong interpretation. Our interpretation is: they cannot do that.

श्री विश्वनाथ पाण्डेय (सलमपुर) : ताशकन्द का यह उद्देश्य था कि दोनों तरफ़ की फौजें 5 अगस्त के स्थान पर पहुंच जायेंगी, लेकिन पाकिस्तान की सरकार सम्बन्धित स्थानों पर अपनी सेनायें इकट्ठा कर रही है। उसी के दबाव से, उसी के बल पर छम्ब सेक्टर से जो भारत का स्थान है, वह वापस नहीं जाना चाहती है। मैं जानना चाहता हूं कि इस के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ? इस के साथ साथ....

अध्यक्ष महोदय : एक ही सवाल रखिये ।

श्री विश्वनाथ पाण्डेय : इसके साथ साथ जब दोनों तरफ से फौजें हटाई गईं उससे पहले तक जब पाकिस्तान के सैनिक वहां पर डटे हुए थे, तब सीमांत के जो गांव थे वहां के रहने वालों को शस्त्र अपनी रक्षा के लिए दिये गये थे लेकिन फौजों के हट जाने के बाद यह जो जमाव हुआ है इसके कारण वहां के लोगों में काफी आतंक की भावना पैदा हो गई है और इस कारण से राजस्थान के सीमान्त के गांवों को लोग छोड़ कर आ रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि उन लोगों की सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था सरकार कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : बहुत से सवाल एक साथ किये जायें तो मिनिस्टर साहिबान एक ही सवाल का जवाब दे दिया करें तो मैं काफी समझूंगा ।

Shri Y. B. Chavan: Sir, according to my information they have withdrawn from the Chamb area and even from the Rajasthan area also. They have withdrawn and gone back to the 5th August line (*Interruption*). This is one question that he has raised and I am trying to answer only that question. He has raised many other questions. He has raised the question about some fear complex prevailing in some of the villages on our side of the border. I have not got any information about it from the Rajasthan Government. If at all there is some sort of fear complex in the minds of our people on our side of the villages, I am sure the Rajasthan Government must be taking necessary steps about it.

Shri Kapur Singh (Ludhiana): Are Government prepared to meet adequately a concerted Pak-Chinese aggression against India today or tomorrow? That is what we want to know.

Shri Y. B. Chavan: Yes.

श्री राम हरख यादव (आजमगढ़) : पाकिस्तान ताशकंद समझौते के बाद भी सरहदों पर अपनी फौजें जमा कर रहा है । हाल में जो घटनायें घटी हैं उन से ऐसा भी मालूम होता है कि पाकिस्तान हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है । चीन के सब से बड़े जो अधिकारी हैं वह वहां पर मौजूद हैं । इसके साथ साथ पचास चीनी टैंकों और पचास चीनी मिग विमानों का भी अभी वहां पर प्रदर्शन किया गया है । इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ऐसे कौन से कदम उठा रही है या उठाना चाहती है ताकि जो खतरे पैदा हो रहे हैं वे न हों और पाकिस्तान ताशकंद समझौते का पालन करे ? मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिए क्या तरकीब की जा रही है ?

Shri Y. B. Chavan: Sir, if I have understood the hon. Member, his point is whether there is any unusual concentration on the other side of the border. As I said in my statement, we are aware of the presence of Pakistani troops on their side of the border, but I have not yet come across any unusual concentration, as you may call it, or any concentration which might indicate any offensive posture at the present moment. I can only say that we have taken all steps about defensive measures in regard to this particular matter. That is all that I can say.

Shri Harish Chandra Mathur (Jalore): This concentration on the borders apart, may I know what are the other warlike preparations which have come to the notice of the hon. Minister—regarding arms and ammunitions, getting Chinese leaders, their pacts with them etc., and what is his reaction?

Shri Y. B. Chavan: Warlike preparation is in their attitude, the way they are talking about Tashkent, the way they paraded the Chinese equipment, the way the Chinese reacted after the President's visit and so on. These are some of the indications which, really speaking, call for us to be wide awake, and we cannot afford to be complacent about this matter.

श्री हुकम चन्द कछवाय (देवास) : ताशकंद समझौता जो हुआ है यह क्या इसलिए हुआ है कि दोनों साइड्ज इसको मानें या केवल एक साइड माने ? इसको एक तरफ से तो ठुकराया जा रहा है और दूसरी तरफ से माना जा रहा है । ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री पर रूस द्वारा दबाव डाला गया था और कहा गया था कि आप ताशकंद समझौता नहीं करेंगे तो हम भारत को मदद नहीं देंगे । अभी अमरीका में हमारे प्रधान मंत्री गए हुए हैं । टाइम में एक लेख छपा है जिसमें कहा गया है कि यदि भारत काश्मीर के सम्बन्ध में पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहता है तो हम उसे किसी प्रकार की मदद नहीं देंगे । जिस तरह से रूस के सामने झुक कर हमने ताशकंद समझौता किया है उसी तरह से अमरीका के सामने झुक कर हम इस प्रकार की बातचीत करने को तैयार हो जायेंगे । मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

Shri Y. B. Chavan: The relevant part of the question was about the Tashkent Declaration, whether it is binding on both the parties. Obviously, any agreement is binding on both the parties. It cannot be binding on merely the Indian side. There was no question of coercion or pressure on India to accept the Tashkent Agreement.

Shri Karni Singhji (Bikaner): With the background of the Pakistani bombing of some of our border cities like Jodhpur, Amritsar and Ferozepur, I would like to know if Government have taken adequate steps for the defence of our cities all along the border by providing them with anti-aircraft guns, fighter aircraft bases within striking distance, speeding up of the building of border roads and the sinking of tubewells in the desert areas for providing water to our soldiers?

Shri Y. B. Chavan: The hon. Member has made very useful suggestions on this question. The air defence of any particular city certainly raises many questions, many aspects, of which communication is very important. Government have taken certain steps in the matter. About the wells to which he made a reference, I will have to look into it.

श्री हुकम चन्द कछवाय : एक भाग का उत्तर नहीं आया है ।

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाइये । उसके बाद भी सवाल हो गया है ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : ताशकंद समझौते के बाद दोनों देशों की जनता में तो कम-अज कम शांति की लहर दौड़ी थी । अब कुछ छुटपुट घटनायें हो रही हैं और ऐसे समाचार भी आ रहे हैं कि पाकिस्तान ताशकंद ऐग्रीमेंट का उल्लंघन कर रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि इन सब चीजों के बारे में सोवियत यूनियन को आपकी तरफ से लिखा गया है ? यदि हां तो उसकी क्या प्रतिक्रिया है ?

दूसरे कौन सा हम ऐक्शन ले रहे हैं जिससे ताशकंद ऐग्रीमेंट जिन्दा रहे ? ऐसा न हो कि उसको पाकिस्तान दफना दे ।

Shri Y. B. Chavan: I said about this attitude of some of the leaders on Pakistan side to the Tashkent Declaration. I did make a reference to it. Naturally, we are keeping the Russian Government, Russian authorities informed from time to time as to what is happening. I am sure the Russians themselves are watching this very carefully. On our side I think we should not show any weakness in observing the Tashkent Declaration. We should strictly follow the Tashkent Declaration, as we have agreed to..

श्री मौर्य (अलीगढ़) : ताशकंद समझौते के बाद पाकिस्तान का जो रवैया रहा

है और जो उनके बयान आये हैं, और उसके बाद अब पंजाब और राजस्थान की सीमाओं पर उनकी फौजों का दबाव जो बढ़ता जा रहा है, इन तमाम बातों को ले कर हिन्दुस्तान की सरकार ने क्या पाकिस्तान की सरकार को कोई विरोधपत्र लिखे हैं और अगर लिखे हैं तो क्या उनको सदन पटल पर रखा जाएगा ? पाकिस्तान सरकार की तरफ से जो उनके उत्तर आए हैं — आए हैं तो—उनको भी सदन पटल पर रखा जाएगा क्या ?

Shri Y. B. Chavan: Sir, some of these questions like writing to the Pakistan Government are dealt with normally by the External Affairs Ministry. I will have to consult them in this matter before I say anything about it.

Shri Maurya: My question is different. Have you written to them? Have you protested to them?

Shri Y. B. Chavan: In some cases "yes".

Shri Maurya: Have you received their reply?

Shri Y. B. Chavan: I think the hon. Member is certainly entitled to cross-examine me. I do not deny him that right. But what I am saying is that the writing notes etc. are done by the External Affairs Ministry. I will have to consult them before I give any reply.

Shri P. C. Borooah (Sibsagar): May I know whether concentration and re-mobilisation of Pakistani troops are aimed at spoiling the prospect of aid by USA to India and to make USA impress upon our Prime Minister that she should negotiate on Kashmir with Pakistan before getting food supplies? Have Government received any such indication?

Shri Y. B. Chavan: Really speaking, by asking that question the hon. Member is giving his own assessment of the intentions of Pakistan. I can say, well, it is quite possible that they may be their intentions; may be also that they are trying to impress their own people and trying to cover up their weakness. I do not know.

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : पिछले सितम्बर महीने में राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में हमारी 24 चौकियों पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा किया था । मैं जानना चाहता हूं कि कब्जा करने के कितने दिन बाद इस सत्य को इस सदन के सामने प्रकट किया गया था और उसी से मेरा यह सवाल उठता है कि पाकिस्तानी सेना का इस वक्त जो जमाव है वह पाकिस्तान की भूमि पर है या हमारी जो भूमि है उस पर भी अब जमाव पाकिस्तानी सेना का कायम हो गया है ?

अध्यक्ष महोदय : जो दूसरा सवाल है उस का ही जवाब दिया जाये ।

Shri Y. B. Chavan: There are no troops on our side of the border; whatever troops are there are on their side of the border.

श्री मधु लिमये : पहले का जवाब क्यों नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उस की इजाजत नहीं दी ।

श्री मधु लिमये : मैंने इस लिये पूछा कि हमेशा की यह परिपाटी हो गई है . . .

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि अब आप बैठ जाइये ।

श्री मधु लिमये : पहले तो इन्कार करते हैं लेकिन जब सत्य सामने आता है, और कई दफे ऐसा हुआ है, चीनी आक्रमण के बारे में हुआ, पाकिस्तान के आक्रमण के बारे में हुआ . . . .

अध्यक्ष महोदय : इस का इस सवाल से कोई मतलब नहीं है ।

श्री मधु लिमये : इस तरह से यहां सत्य को सरकार छिपाती है और हमें मेहनत कर के उसे सामने लाना पड़ता है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : (फर्रुखाबाद): मंत्री जी ने अभी इसी जगह दो बातें कहीं । एक तो यह कि ताशकन्द घोषणा का सख्ती से पालन होगा और दूसरे यह कि सीमाओं पर सावधानी से नजर रक्खी जा रही है । सावधानी की नजर हमेशा गड़बड़ी की शुरूआत होती है । उन्होंने यह दोनों बातें कहीं इस लिये क्या सरकार अब इस मामले पर व्यापक दृष्टि रखने के लिए, एक प्रस्ताव पर विचार कर चुकी है कि जैसे महात्मा गांधी की हत्या के सम्बन्ध में एक आयोग उसने बिठाया वैसे ही इस देश के भारत और पाकिस्तान में बटवारे पर एक आयोग बिठलाये । अगर उस ने विचार किया है तो कब तक यह आयोग बैठ जायेगा ।

Shri Y. B. Chavan: There is no question of appointing a commission on this.

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय,

अध्यक्ष महोदय : इस सवाल का इससे कोई ताल्लुक नहीं है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : अगर हमेशा इस तरह से रोकेंगे तो यह मुल्क बरबाद होता चलेगा . . .

अध्यक्ष महोदय : मैं तो कोई रोक काम नहीं कर सकता ।

डा० राम मनोहर लोहिया : तब फिर आप भी बरबादी में हिस्सा लेंगे ।

12.32 hrs.

PAPER LAID ON THE TABLE

ANNUAL ACCOUNTS OF THE COMMISSIONERS FOR THE PORT OF CALCUTTA AND AUDIT REPORT

The Minister of State in the Ministry of Transport and Aviation (Shri C. M. Poonacha): With your permission, Sir, I beg to lay on the Table of the House, on behalf of Shri Sanjiva Reddy, a copy of the Annual Accounts of the Commissioners for the Port of Calcutta for the year 1963-64 along with the Audit Report thereon. [*Placed in Library. See* No. LT-5922/66].

12.32½ hrs.

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

Secretary: Sir, I have to report the following messages received from the Secretary of Rajya Sabha:—

(1) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha, at its sitting held on the 28th March, 1966, agreed without any amendment to the Armed Forces (Special Powers) Amendment Bill, 1966, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 21st March, 1966."

(2) "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Appropriation Bill, 1966, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 22nd March, 1966, and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."